The Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Managment (Amendment) Act, 2010

Act 7 of 2010

Keyword(s):
FRBM

Amendments appended: 8 of 2011, 12 of 2020, 22 of 2020, 34 of 2020

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

Registered No. HSE/49 [Price : Rs. 0-30 Paise.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART IV-B EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 11] HYDERABAD, THURSDAY, APRIL 15, 2010.

ANDHRA PRADESH ACTS, ORDINANCES AND REGULATIONS Etc.

The following Act of the Andhra Pradesh Legislature, received the assent of the Governor on the 13th April, 2010 and the said assent is hereby first published on the 15th April, 2010 in the Andhra Pradesh Gazette for general information.

ACT No. 7 OF 2010.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE ANDHRA PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Sixty first year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Managment (Amendment) Act, 2010. **Short title and commen-cement.**

A. 690/

(2) It shall be deemed to have come into force with effect on and from the 3rd June, 2005.

Amendment of section 9. Act 34 of 2005.

2. In the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in section 9, in sub-section (2) for clause (b) and the proviso thereunder, the following shall be substituted, namely,-

"(b) reduce fiscal deficit by an amount equivalent to atleast 0.25 percentage point of Gross State Domestic Product in each financial year beginning from the 1st day of April, 2005, so as to bring it down to not more than 3 percent; subject to the fiscal deficit limits fixed by the Government of India from time to time:

Provided that for the financial year ending March, 2009 the fiscal deficit shall not be more than 3.5 percent of G.S.D.P. and for the financial year ending March, 2010 the fiscal deficit shall not be more than 4 percent of G.S.D.P."

R. RAMA CHANDRA REDDY,
Secretary to Government,
Legislative Affairs & Justice,
Law Department.

PRINTED AND PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF PRINTING,
AT LEGISLATIVE ASSEMBLY PRESS, HYDERABAD.

Registered No. HSE/49 [Price : Rs. 0-30 Paise.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART IV-B EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 8] HYDERABAD, THURSDAY, MARCH 31, 2011.

ANDHRA PRADESH ACTS, ORDINANCES AND REGULATIONS ETC.

The following Act of the Andhra Pradesh Legislature, received the assent of the Governor on the 31st March, 2011 and the said assent is hereby first published on the 31st March, 2011 in the Andhra Pradesh Gazette for general information.

ACT No. 8 OF 2011.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE ANDHRA PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005.

Be it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Sixty- second year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect on and from the 1st April, 2010.

Amendment of section 9. Act 34 of 2005.

2. In the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in section 9, in sub-section (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:–

"(cc) ensure within the subsequent period of five years, beginning from the financial year on the 1st day of April, 2010, and ending on the 31st day of March, 2015, that the total outstanding liabilities do not exceed 27.6 percent of the GSDP, as prescribed by the Government of India in pursuance of the recommendations of Thirteenth Finance Commission, year wise as follows:

for the financial year 2010-11	30.3 percent of GSDP
for the financial year 2011-12	29.6 percent of GSDP
for the financial year 2012-13	28.9 percent of GSDP
for the financial year 2013-14	28.2 percent of GSDP
for the financial year 2014-15	27.6 percent of GSDP".

A. SHANKAR NARAYANA,
Secretary to Government,
Legislative Affairs & Justice,
Law Department.

PRINTED AND PUBLISHED BY THE COMMISSIONER OF PRINTING, AT LEGISLATIVE ASSEMBLY PRESS, HYDERABAD, 2011.

क्रम-संख्या–131

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020

भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1578/79–वि–1-20-1(क)15-20
लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 31 मार्च, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

184 RPH (Budget Amendment) 2020 data 11

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में,–

(क) खण्ड (ग) के उपखण्ड (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह भी कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 में राजकोषीय घाटे की अधिकतम सीमा में, वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।";

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह कि वित्तीय वर्ष 2019–2020 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टॉक में, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य की गयी अतिरिक्त ऋण की धनराशि रुपये 10,570 करोड़ की वृद्धि की जायेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020

3–(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार करने और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान निम्नतर कर राजस्व संग्रह के कारण वित्तीय वर्ष 2019–2020 में राज्यों के केन्द्रीय कर अंश के सापेक्ष 58,843 करोड़ रुपये का समायोजन किया है। राज्यों के केन्द्रीय कर अंश में गिरावट के कारण राज्य संसाधनों में कटौती को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 में संशोधन के अध्यधीन एक बार की विशेष व्यवस्था स्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को वित्तीय वर्ष 2019–2020 में 10,570 करोड़ रुपये की अतिरिक्त ऋण दिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूँकि, राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2020 को उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे०पी० सिंह–II,
प्रमुख सचिव।

No. 1578(2) /LXXIX-V-1–20-1(ka)15-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-1, is administratively concerned with the said adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 12 OF 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on March 31, 2020.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 in sub-section (3),–

(a) *after* sub-clause (i) of clause (c), the following proviso shall be *inserted*, namely :–

"Provided also that the ceiling of fiscal deficit in the fiscal year 2019-2020 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10,570 crore, allowed by the Government of India, over and above the ceiling of 3 per cent of the estimated Gross State Domestic Product for the fiscal year 2019-2020.";

(b) *after* clause (f), the following proviso shall be *inserted*, namely :–

"Provided that the total debt stock at the end of the fiscal year 2019-2020 shall be enhanced by an additional borrowing of Rupees 10,570 crore allowed by the Government of India, over and above 30 per cent of the estimated Gross State Domestic Product for the fiscal year 2019-2020."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 3 of 2020

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for improving social and fiscal infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government's borrowings Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

The Government of India, has adjusted Rs. 58,843 crore against the States' share of Central taxes in the fiscal year 2019-20, on account of lower tax revenue collection during the year 2018-2019. In view of reduction in states' resources due to fall in states' share in Central taxes, the Government of India, has allowed the State of Uttar Pradesh an additional borrowing of Rs. 10,570 crore in the year 2019-20 as a one-time special dispensation subject to the amendment of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 for the year 2019-20. In view of the above it had been decided to amend the said Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate Legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 (U. P. ordinance no. 3 of 2020) was promulgated by the Governor on March 31, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J.P. Singh-II,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 184 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(550)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 142 सा0 विधायी–2020–(551)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

184 RPH (Budget Amendment) 2020 data 11

क्रम-संख्या–148

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 31 अगस्त, 2020
भाद्रपद 9, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1569 / 79–वि–1-20-1(क) 25-20
लखनऊ, 31 अगस्त, 2020

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 जिससे वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 28 अगस्त, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2020 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2020)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 19 जून, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा 4 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा 4 में, उपधारा (3) में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ग) वित्तीय वर्ष 2020–2021 में राजकोषीय घाटा, प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक पाँच प्रतिशत पर बनाये रखेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2020

3–(1) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

राजकोषीय स्थायित्व और संपोषणीयता सुनिश्चित करने और पर्याप्त राजस्व अधिशेष की प्राप्ति करके राजकोषीय घाटे में कमी लाकर और राजकोषीय नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली अड़चनों को दूर करने और राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाले उधारों, सरकारी प्रत्याभूतियों, ऋणों और घाटों पर सीमा निर्धारण और मध्यकालिक राजकोषीय रूपरेखा के प्रयोग में महत्तर पारदर्शिता के माध्यम से विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्ध द्वारा सामाजिक और भौतिक अवसंरचना में सुधार करने और मानव विकास के अवसर में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व की व्यवस्था करने के लिये उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 अधिनियमित किया गया है।

कोविड–19 महामारी के कारण राज्य एवं केन्द्र के संसाधनों पर गम्भीर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उक्त के दृष्टिगत अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2 प्रतिशत की अतिरिक्त ऋण सीमा, वित्तीय वर्ष 2020–2021 के लिये अनुमन्य की गयी है, जिसके लिये राज्य सरकारों से अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में संशोधन करने की अपेक्षा की गयी थी। अतएव पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि राज्य विधानमण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिय तुरन्त विधायी कार्यवाही करनी आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 19 जून, 2020 को उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13 सन् 2020) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने हेतु पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

जे०पी० सिंह–II,

प्रमुख सचिव।

No. 1569(2) /LXXIX-V-1-20-1(ka) 25-20

Dated Lucknow, August 31, 2020

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajkoshiya Uttardayitwa Aur Budget Prabandh (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2020 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 22 of 2020) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2020. The Vitta (Aay-Vyayak) Anubhag-1, is administratively concerned with the said adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT (SECOND AMENDMENT) ACT, 2020

(U.P. Act no. 22 OF 2020)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy First Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from June 19, 2020.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 5 of 2004

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 in sub-section (3) *for* clause (c) the following clause shall be *substituted*, namely :–

"(c) maintain fiscal deficit at not more than five per cent of the estimated Gross State Domestic Product in the fiscal year 2020-2021."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 13 of 2020

3. (1) The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2004 has been enacted to provide for the responsibility of the State Government to ensure fiscal stability and sustainability and to enhance the scope for social and fiscal infrastructure and human development by achieving sufficient revenue surplus, reducing fiscal deficit and removing impediments to the effective conduct of fiscal policy and prudent debt management through limits on State Government's borrowings Government guarantees, debt and deficit, greater transparency in fiscal operations of the State Government and use of a medium term fiscal framework.

The COVID-19 pandemic has adversely affected the resources of the States and the Centre. In view of the above, to raise additional resources, the Central Government has allowed an additional borrowing limit of 2 per cent of the Gross State Domestic Product to the State Governments for the financial year 2020-2021. For which State Governments were required to amend their Fiscal Responsibility and Budget Management Act. Therefore, it was decided to amend the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Second Amendment) Ordinance, 2020 (U. P. ordinance no. 13 of 2020) was promulgated by the Governor on June 19, 2020.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 201 राजपत्र–(हिन्दी)–2020–(584)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 159 सा० विधायी–2020–(585)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

201 RPH (Budget Amendment-II) 2020 data 11

Registered No. HSE/49. [Price : Rs.1.00 Paise

RIGHT TO INFORMATION

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజపత్రము

THE ANDHRA PRADESH GAZETTE

PART IV-B EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 34] AMARAVATI, WEDNESDAY, 23rd DECEMBER, 2020.

ANDHRA PRADESH ACTS, ORDINANCES AND REGULATIONS Etc.,

The following Act of the Andhra Pradesh Legislature received the assent of the Governor on the 18th December, 2020 and the said assent is hereby first published on the 23rd December, 2020 in the Andhra Pradesh Gazette for general information :

ACT No. 34 of 2020.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE ANDHRA PRADESH FISCAL RESPONSIBILITY AND BUDGET MANAGEMENT ACT, 2005

Be it enacted by the Legislature of the State of Andhra Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows,-

1. (1) This Act may be called the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Act, 2020. *Short tiltle and commencement.*

(2) It shall be deemed to have come into force on and from the 30th day of August 2020.

2. In the Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management Act, 2005, in sub-section (2) of section 9,- *Amendment of section 9.*

(i) the following provisos shall be added to clause (a), namely, - *Act No. 34 of 2005.*

"Provided that for the financial years from 2015-16 to 2019-20, the Revenue Deficit shall not be more than 2.5 % of GSDP including onetime additional borrowing of Rs. 2,534 crore permitted by Government of India for the year 2019-20.

Provided further that for the financial year ending March 2021, the Revenue Deficit shall be contained within 4.5% of GSDP and reduced progressively thereafter.".

(ii) The following proviso shall be added after existing proviso to clause (b), namely,-

"Provided further that for the financial years from 2015-16 to 2020-21, the Fiscal Deficit shall not be more than 5 % of GSDP, including onetime additional borrowing of Rs. 2,534 crore permitted by Government of India for the year 2019-20 and including 2% of GSDP additional borrowing permitted by Government of India for FY 2020-21 in the wake of Covid-19 pandemic, and sought to be progressively reduced thereafter.".

(iii) after clause (cc), the following clause shall be inserted, namely,-

"(ccc) ensure that for the financial years from 2015-16 to 2020-21, the outstanding total liabilities do not exceed 35 per cent of the estimated GSDP and maintain thereafter, including onetime additional borrowing of Rs. 2,534 crore permitted by Government of India for the year 2019-20 and 2% of GSDP additional borrowing permitted by Government of India for FY 2020-21 in the wake of Covid-19 pandemic.".

Repeal of Ordinance No.9 of 2020.

3. The Andhra Pradesh Fiscal Responsibility and Budget Management (Amendment) Ordinance, 2020 is hereby repealed.

VADDADI SUNITHA,
Secretary to Government (FAC),
Legal and Legislative Affairs & Justice,
Law Department.

Printed by the Commissioner of Printing at A.P. Legislative Assembly Printing Press, Amaravati.